भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1333

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

छात्रों के आधार कार्ड में विसंगतियां

1333. **श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के सरकारी और अर्ध-सरकारी विद्यालयों में नामांकित लगभग चार लाख आठ हजार छात्रों के आधार कार्ड में विसंगतियां पाई गई हैं और उनमें से लगभग तीन लाख बाईस हजार छात्र अमान्य घोषित कर दिए गए हैं यदि हां, तो विसंगतियों के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त विसंगति के कारण कितने छात्र विभिन्न शैक्षिक योजनाओं और छात्रवृत्ति सहित लाभों से वंचित हो रहे हैं और सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त विसंगतियों को दूर करने और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): महाराष्ट्र में स्कूल छात्रों के आधार पंजीकरण की स्थिति और उनके आधार विवरणों को मान्य करने संबंधी प्रगति, जैसा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार है:

क्रमांक		संख्या
1	कुल छात्र	1,84,89,092
2	आधार उपलब्ध नहीं कराया गया	4,55,263
3	लंबित आधार अधिप्रमाणन	6,80,686
4	विफल आधार अधिप्रमाणन	2,08,903
5	सफल आधार अधिप्रमाणन	1,71,44,240
6	केवल सत्यापित आधार	1,70,36,596

* स्रोत: यूडाइज़+ डाटा

राज्य ने सूचित किया है कि सत्यापन में विफलता के सामान्य कारणों में नाम, वर्तनी, जन्मतिथि (डी.ओ.बी.) में विसंगति, आधार कार्ड का अद्यतन न होना, आधार कार्ड में जन्मतिथि का न होना, राज्य के सरल पोर्टल पर पंजीकरण करते समय त्रुटियां, जेंडर विसंगति आदि शामिल हैं। आधार कार्ड में नए नामांकन और सुधार का कार्य ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर एक सतत प्रक्रिया है, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने महाराष्ट्र के प्रत्येक ब्लॉक में आधार से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए दो आधार किट विकसित किए हैं। इसके अलावा, आधार अमान्य होने के कारण किसी भी छात्र को योजनाओं और छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित नहीं किया गया है।

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र छात्र इस विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें, जिसमें समग्र शिक्षा और पीएम-पोषण जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है। इस उद्देश्य से, यह विभाग निरंतर समीक्षा करता है तथा परियोजना मूल्यांकन बोर्ड (पीएबी) और राज्यों के साथ त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से जमीनी स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

******